450 people are without employment and the Government—the Maharashtra Government und the Central Government—;»r$_e$ doing nothing and sitting tight. 1 appeal to you that it is a serious matter. Though we talk of industrial growth, nothing is done for the workers. . And this is a matter where the Government should intervene.

REFERENCE TO THE NEED TO PROVIDE BETFER FACILITIES TO HAJ PILGRIMS

श्री हुकमदेव नारायण यादव (बिहार) : महोदया, मैं सरकार और सदन का ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं और विषय यह है कि हमारे देश के लाखों मुसलमान भाई अपने तीर्थस्थल पर हज करने के लिए साल में जाया करते हैं केवल बड़े लोगों ही जिनके पास पैसे हैं वही अगर तीर्थस्थल तक जाय तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है। जो गरीब आदमी हैं, साधारण, मध्यम या अल्प आय वाले हैं उनकी दिल में यह भावना है कि वे भी अपने तीर्थस्थल पर जाने और वहां जाकर हज कर सकें। परन्तु जाने की सुविधा न होने, हवाई जहाज का किराया बहुत ज्यादा होने से जो अल्प आय वाले या मध्यम आय वाले हैं वे जा नहीं पाते। पानी के जहाज से यात्रा करने की जो सुविधा है वह कम है स्टीमर न रहने के कारण। इस कारण गरीब लोग अपने तीर्थस्थल तक नहीं पहुंच पाते। तो सरकार का कर्तव्य यह होना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे सस्ती यात्रा का प्रबन्ध हो। जो कम से कम पैसे पर सरकार से अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त कर के अपने तीर्थस्थल पर जा कर अपनी भावना के उद्गार को प्रकट कर सकें और वहां जा कर अपने तीर्थस्थल के दर्शन कर सकें। यह एक आवश्यक सवाल है जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए। सरकार करोड़ों रुपया दूसरी चीजों पर खर्च करती है इस लिये यदि कुछ रुपया सरकार का इस के लिये खर्च हो जाय तो क्या बिगड़ जायेगा। सरकार को इस में अभिरुचि लेना चाहिए। पासपोर्ट और वीजा का जो सवाल है वे अन्य लोगों को जो दिये जाते हैं उस के बनिस्बत जो हज यात्री है उन के लिये अधिक सुविधा वाली व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सहूलियत से उन को पासपोर्ट मिल जाय, वीजा मिल जाय और अपने तीर्थ स्थल तक पहुंचने के लिये उन को सवारी भी मिल जाय। और अन्य दूसरी सुविधायें भी मिल जायें। इस देश में मुसलमानों की संख्या कम नहीं है और उन के तीर्थस्थल चूंकि देश के बाहर है और उन को वहां जाना होता है इसलिये मेरी प्रार्थना है कि अब उन के जाने का समय आने वाला है। हमारे इलाके के लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि तो मुसलमानों की आबादी सब से अधिक है। उन्होंने इस बारे में अपनी कठिनाई मुझे बतायी और इसलिये मैंने उन से कहा कि मैं सरकार के सामने इस बात को रखूंगा और उन की भावना को मैं आप के सामने रख रहा हूं और चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे और कोई ऐसी व्यवस्था करे कि उन को कम से कम खर्च में अपने तीर्थस्थल में जाने की सुविधा सरकार की ओर से मिल सके। यह मेरा आग्रह है।

THE CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL, 1985, (CONTINUED)

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up further consideration of the Citizenship (Amendment) Bill, 1985.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SITARAM KESRI): Madam, I have a request to make since the Deputy Chairman yesterday asked the Minister to reply...

THE DEPUTY CHAIRMAN: You mean Vice-Chairman.

SHRI SITARAM KESRI: I am sorry Madarn,, it was Vice-Chairman. .. .but some hon. Members are still left who want to speak. I shall, therefore, request that they may be allowed to spetk.

THE DEPUTY CHAIRMAN: How many are they?

SHRI SITARAM KESRI: Only two or three.

THE DEPUTY CHAIRMAN: All right. Mr. Rafique Alam.

श्री रफीक आलम (बिहार) : मोहतरिमा डिप्टी चेयरमैन साहिबा, मैं आप के जरिये सरकार को दिली मुबारकबाद देता हूं कि सरकार ने इस सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल 1985 को हाउस में पेश किया है। मैं इस की ताईद करता हूं।

यह बिल बहुत छोटा सा बिल है। इस को तो बगैर बहस मुबाहिसे के पास कर देना चाहिए था इसलिये कि यह तो "Too much ado about nothing". वाली बात है। यही अपोजीशन वाले लोग कर रहे हैं। इस बिल में उन मासूमों मजबूरों और मुसीबतजदा लोगों की आवाज है जो हिन्दुस्तान में रहते हुए बंगला देश चले गये थे और बंगला देश से जब वापस आये तो वहां आंसू और जन संग्राम परिषद् के वर्कर्स ने उन को तबाह और बर्बाद किया। सरकार ने कुछ मजबूरी के तहत उस को बर्दाश्त किया। मुझे आसाम जाने का मौका मिला। मैंने वहां के लोगों से पूछा और उन से मिला तो ख्वाह वे हिन्दू भाई हों या मुसलमान हों और जो किसी न किसी वजह से बंगला देश चले गये थे और फिर वापस आये वे कह रहे थे कि अगर दस साल के लिये आपने वोट से हमको वंचित कर दिया तो हम हिन्दुस्तान के शहरी कैसे रहेंगे। यह शहरी हकूक हम को कैसे मिलेंगे। हमारी जायदादों का क्या होगा ? हमारे मकानात का क्या होगा हम को तो आप ने उजाड़ दिया। तो इस बिल में यह लाया गया कि नहीं, आप दस साल के लिये वोटिंग राइट से वंचित हैं लेकिन आप के शहरी हकूक सब आप को मिलेंगे अभी भी और बाद में भी। तो कौन सा बुरा काम सरकार ने किया। अगर उन के हकूक को कांस्टीट्यूशनल हक दिया गया तो इस में कौन सी बुराई थी और फिर कुछ लोग कहते हैं कि यह अनकांस्टीट्यूशनल है। तो कास्टीट्यूशन आफ इंडिया ही हमारा कांस्टीट्यूशन है। हमारा कोई दूसरा कांस्टीट्यूशन नहीं है। इस में आर्टिकल 11 में साफ तौर से जाहिर है लिखा है कि "Parliament to regulate the right of citizenship by lew." तो जब पार्लियामेंट को अधिकार है कि वह जब चाहे तो चेंज करे या उस के लिये कानून लाये तो यह अन-कांस्टीट्यूशनल कैसे हुआ ? और उसमें क्लीयर है।

"Nothing in the foregoing provisions of this Pait shall derogate from the power, of Parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship."

तो यह कानूनी हक तो जायज है। इसलिये मैंने पहले ही कहा कि मुबारकबाद देता हूं। बिल सरकार लाई तो इसमें कोई पालिटिकल मोटिव नहीं है। इसमें इंसानियत की अवाज जरूर है। वे लोग जो बेघरबार हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं हमने उन लोगों को हकूक दिये। इसलिए हमें तो यह चाहिए था कि इस बिल को बिना किसी डिस्कशन के पास करते। बहुत से लोग कह रहे हैं कि 60 दिन बहुत कम हैं। मैं इससे इत्तफाक करता हूं कि। 60 दिन बहुत कम हैं यें कम से कम 90 दिन होने चाहिए अपील करने के लिये और इसमें कोई दो राय नहीं हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो लोग यह कहते है कि सरकार ने वायलेंस के सामने सिर झुका दिया या घुटने टेक दिए यह बिल्कुल गलत है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि चाहे पंजाब का अकार्ड हो या असम का अकार्ड हो, किन हालात में अकार्ड किया गया, यह आपको पता है। आपको हालात के बारे में बताऊं तो आप भी कहेंगे कि कितने बुरे हालात थे। एक तरफ तो जलता हुआ पंजाब था, दूसरी तरफ टूटता हुआ

हिन्दुस्तान, तीसरी तरफ श्रीमती इन्दिरा गांधी जिनका बदन गोलियों से छलनी कर दिया गया था, वह सब राजीव जी के सामने उनकी आंखों के सामने था जब वह अकार्ड पर दस्तखत कर रहे थे। जो असम का अकार्ड हुआ उस पर रात को तीन बजे 15 अगस्त, 1985 को दस्तखत हुए। राजीव जी हमेशा यही चाहते रहे कि मुल्क में अमन-चैन कायम रहे। उनके सामने मासूम बच्चों की लाशें, बेगुनाह औरतों की लाशें पड़ी हुई थीं। उन्होंने देखा कि अगर असम में हमने अमन कायम नहीं किया तो यह आसाम जल जायेगा। बाहरी ताकतें हमारे मुल्क के अंदर घुस जायेंगी और हम को तबाह और बर्बाद कर देंगी। अगर राजीव जी ने यह किया तो क्या गलत किया। मैं पूछना चाहता हूं कि सदन के माननीय सदस्यों से उन्होंने सही हालात के तहत यह काम किया मुल्क में अमन कायम करने के लिए चाहे पंजाब हो या असम तो क्या गलत किया। कांग्रेस ने कभी वायलेंस के सामने सिर नहीं झुकाया। अगर कांग्रेस वायलेंस के सामने सिर झुकाती तो हिन्दुस्तान आजाद नहीं होता। याद रखिये कि महात्मा गांधी ने अपनी सारी जिन्दगी जेल में गुजारी, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने अपनी जवानी को नहीं देखा, आनन्द भवन को नहीं देखा, सूरज भवन को नहीं देखा। उन्होंने अंग्रेजों के सामने अपना सीना तान दिया। उन्होंने नन्ही सी इन्दिरा जी के जो जजबात थे उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और मुल्क आजाद हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने वायलेंस पर सिर झुकाया है यह गलत है। यह कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि जहां उन्होंने आजादी दिलाई वहां वह उस आजादी की हिफाजत भी करे। इस मुल्क को हमने टूटने नहीं देना है।

मैं आपके जरिये, आपके माध्यम से समूह से अपील करना चाहता हूं इस मुल्क को लाखों कुर्बानियां देने के बाद आजाद कराया गया हम सब का यह फर्ज है कि इस मुल्क की हिफाजत करें। यह कहा गया है Eternal vigilance is the price of liberty. इसलिए हम लोगों को विजिलेंट रहना है जब भी मैं यह सुनता हूं कि हिन्दू और मुसलमान के झगड़े हुए हैं या फसादात हुई हैं तो मेरा कलेजा मुंह को आता है। ये एक ही हिन्दुस्तान के लोग हैं—चाहे हिन्दू हों या सिख हों, मुसलमान हों या ईसाई हों, अगर वे हिन्दुस्तान में घर जला रहे हैं, कारखाने जला रहे हैं, घर तबाह कर रहे हैं तो वे इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। यह घर न पाकिस्तान का है, न चीन का है और न किसी और का घर है। यह घर हिन्दुस्तान का है। सब कारखाने हिन्दुस्तान के हैं। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हम मुसलमान भाई, हिन्दू भाई, सिख भाई और ईसाई भाई सब हिन्दुस्तान के रहने वाले हैं। हमने हिन्दुस्तान के कांस्टिट्यूशन की शपथ ली है। हम सब की जान माल की हिफाजत करें और इस मुल्क को एक मजबूत मुल्क बनायें ताकि हिन्दुस्तान का झण्डा कभी झुकने न पाय।

इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

†[شری رفیق عالم (بہار) : محترمہ

ڈپٹی چیئرمین صاحبہ - میں آپکے ذریعہ سرکار کو دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ سرکار نے سٹیزن شپ امنڈ منٹ بل ۱۹۸۵ کو ہاؤس میں پیش کیا ہے - میں اسکی تائید کرتا ہوں -

یہ بل بہت چھوٹا سا بل ہے - اسکو تو بغیر بحث و مباحثہ کے پاس کر دینا چاہئے تھا اس لئے کہ یہ تو ''ٹو مچ ابھاؤٹ نتھنگ'' والی بات ہے - یہی اپوزیشن والے لوگ کر رہے ہیں - اس بل میں ان معصوموں - مجبوروں اور مصیبتزدہ لوگوں کی آواز

†[ ] Translation in Arabic Script.

[شری رفیق عالم]

ہے جو ہندوستان میں رہتے رہتے بنگلہ دیش چلے گئے تھے اور بنگلہ دیش سے جب وہ واپس آئے تو وہاں آسو اور جلسنگرام پریشد کے ورکرس نے انکو تباہ اور برباد کیا - سرکار نے کچھ مجبوری کے تحت اسکو برداشت کیا - مجھے آسام جانے کا موقع ملا - میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا اور ان سے ملا تو خواہ وہ ہندو بھائی ہوں یا مسلمان ہوں جو کسی نہ کسی وجہ سے بنگلہ دیش چلے گئے تھے - اور پھر واپس آئے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر دس سال کے لئے آپ نے ہمیں ووٹ سے ونچت کر دیا تو ہم ہندوستان کے شہری کیسے رہیں گے - یہ شہری حقوق ہمکو کیسے ملیں گے - ہماری جائیدادوں کا کیا ہوگا - ہمارے مکانات کا کیا ہوگا - ہمکو تو آپ نے اجاڑ دیا تو اس بل میں یہ لایا گیا کہ نہیں آپ دس سال کے لئے ووٹنگ رائٹ سے ونچت ہیں لیکن آپ کے شہری حقوق سب آپ کو ملیں گے ابھی بھی اور بعد میں بھی - تو کونسا برا کام سرکار نے کیا اگر انکے حقوق کو کونسٹی ٹیوشنل حق دیا گیا تو اسمیں کونسی برائی تھی اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کونسٹی ٹیوشنل ہے - تو کانسٹی ٹیوشن آف انڈیا ہی ہمارا کانسٹی ٹیوشن ہے - ہمارا کوئی دوسرا کانسٹی ٹیوشن نہیں ہے - اس میں آرٹیکل 11 میں صاف طور سے ظاہر ہے - لکھا کہ . . . .

"پارلیمنٹ تو ریگولیٹ دی رائٹ آف سٹیزن شپ بائی لاء" . . . .

تو جب پارلیمنٹ کو ادھیکار ہے کہ وہ جب چاہے تو چینج کرے یا اسکے لئے قانون لائے تو یہ ان کانسٹی ٹیوشنل کیسے ہوا اور اس میں لکھا ہے :

"Nothing in the foregoing provisions of this Part s! . powers, of Parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship."

تو یہ قانونی حق تو جائز ہے - اسلئے میں نے پہلے ہی کہا کہ مبارکباد دیتا ہوں - بل سرکار لائی تو اسمیں کوئی پولیٹیکل موٹیویشن نہیں ہے - اسمیں انسانیت کی آواز ضرور ہے - وہ لوگ جو بے گھر بار ہو جاتے ہیں برباد ہو جاتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو حقوق دیئے اسلئے ہمیں تو یہ چاہئے تھا کہ اس بل کو بغیر کسی ڈسکشن کے پاس کرتے - بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سات دن بہت کم ہیں میں اس سے اتفاق کرتا ہوں - سات دن بہت کم ہیں یہ کم سے کم 90 دن ہونے چاہئے اپیل کرنے کیلئے اور اسمیں کوئی دو رائے نہیں ہیں - میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار نے وایلنس

کے سامنے سر جھکا دیا یا گھٹنے ٹیک دیئے یہ بالکل غلط ہے - میں صاف طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے پنجاب کا اکارڈ ہو یا آسام کا اکارڈ ہو کن حالات میں اکارڈ کیا گیا - یہ آپ کو پتہ ہے - آپ کو حالات کے بارے میں بتاؤں تو آپ بھی کہیں گے کہ کتنے برے حالات تھے - ایک طرف تو جلتا ہوا پنجاب تھا دوسری طرف ٹوٹتا ہوا ہندوستان تیسری طرف شریمتی اندرا گاندھی جنکا بدن گولیوں سے چھلنی کردیا گیا تھا وہ سب راجیو جی کے سامنے - انکی آنکھوں کے سامنے تھا اب وہ اکارڈ پر دستخط کر رہے تھے - جو آسام کا اکارڈ ہوا اس پر رات کو ۳ بجے ۱۵ اگست ۱۹۸۵ کو دستخط ہوئے - راجیو جی ہمیشہ یہی چاہتے رہے کہ ملک میں امن و چین قائم رہے - انکے سامنے معصوم بچوں کی لاشیں — بیگناہ عورتوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں - انہوں نے دیکھا کہ اگر آسام میں ہم نے امن قائم نہیں کیا تو یہ آسام جل جائیگا - باہری طاقتیں ہمارے ملک کے اندر گھس آئینگی اور ہمکو تباہ اور برباد کردینگی - اگر راجیو جی نے یہ کیا تو کیا غلط کیا - میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سدن کے مانئیہ سدسیوں سے انہوں نے حالات کے تحت یہ کام کیا - ملک میں امن قائم کرنے کے لئے چاہے پنجاب ہو یا آسام تو کیا غلط کیا - کانگریس نے کبھی وائلنس کے سامنے سر نہیں جھکایا - اگر کانگریس وائلنس کے سامنے سر جھکاتی تو ہندوستان آزاد نہیں ہوتا - یاد رکھئے کہ مہاتما گاندھی نے اپنی ساری زندگی جیل میں گزاری - پنڈت جواہر لعل نہرو جی نے اپنی جوانی کو نہیں دیکھا - آنند بھون کو نہیں دیکھا - سوراج بھون کو نہیں دیکھا انہوں نے انگریزوں کے سامنے اپنا سینہ تان دیا - انہوں نے نیتی سی اندرا جی کے جو جذبات تھے اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا اور ملک آزاد ہوا - اسلئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریس نے وائلنس پر سر جھکایا ہے یہ غلط ہے یہ کانگریس کی ذمہداری ہے کہ جہاں انہوں نے آزادی دلائی وہاں وہ اس آزادی کی حفاظت بھی کریں - اس ملک کو ہم نے ٹوٹنے نہیں دینا ہے -

میں آپکے ذریعہ- آپکے مادھیم سے سموہ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اس ملک کو لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد آزاد کرایا گیا - ہم سب کا فرض ہے کہ اس ملک کی حفاظت کریں - یہ کہا گیا ہے ....

اسلئے ہم لوگوں کو ویجیلنٹ رہنا ہے - جب بھی میں یہ سنتا ہوں کہ ہندو اور مسلمان کے جھگڑے ہوئے ہیں یا فسادات ہوئے ہیں - تو میرا کلیجہ منہہ کو آتا ہے - یہ ایک ہی ہندوستان کے لوگ

[شری رفیق عالم]

ہیں - چاہے ہندو ہوں یا سکھ ہوں- مسلمان ہوں یا عیسائی ہوں اگر وہ ہندوستان میں گھر جلا رہے ہیں - کارخانہ جلا رہے ہیں گھر تباہ کر رہے ہیں تو یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں - یہ گھر نہ پاکستان کا ہے نہ چین کا ہے اور نہ کسی اور کا ہے یہ گھر ہندوستان کا ہے - سب کارخانہ ہندوستان کے ہیں - اسلئے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان بھائی ہندو بھائی - سکھ بھائی اور عیسائی بھائی سب ہندوستان کے رہنے والے ہیں - ہم نے ہندوستان کے کانسٹی ٹیوشن کی شپتھ لی ہے - ہم سبکی جان مال کی حفاظت کریں اور اس ملک کو ایک مضبوط ملک بنائیں تاکہ ہندوستان کا جھنڈا کبھی جھکنے نہ پائے -

ان الفاظ کے ساتھ میں اس بل کا سمرتھن کرتا ہوں -]

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : उप-सभापति महोदया, यह जो विधेयक हम लोगों के सामने आया है, अभी कुछ माह पूर्व जो आसाम समझौता हुआ था यह उसके एक छोटे से हिस्से के रूप में है। आसाम के बारे में जो समझौता हुआ है उसका इन लोगों ने पूरा समर्थन किया है । हमने समर्थन इसलिए नहीं किया है कि तमाम समस्याओं का निदान हो गया है । हमने समर्थन इसलिए किया है कि समाधान की, शान्ति की शुरुआत हुई है । हम चाहते हैं कि उस समस्या का पूर्ण निदान करें । यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में बंगला देश से आने वालों की यह एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है । आप जानते हैं कि हमारे देश के दो टुकड़े हो गये । राजनीतिज्ञों ने मिलकर देश के दो टुकड़े कर दिये, लेकिन धरती जहां थी वहीं रही । रिश्तेदार जहां थे वहीं रहे और इस तरह से इधर के लोग उधर आते जाते रहे । आप इसको किस तरीके से रोक सकते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता है । यह एक मानवीय समस्या है, बहुत गम्भीर बात है । यहां से देखने में इस समस्या का सही पता नहीं चलता है । लेकिन अगर आप सीमा पर जायें तो आपको पता चलेगा कि यहां भारत का किसान अपना हल लेकर खेत जोतने के लिए वहां बंगला देश जाता है क्योंकि उसकी जमीन वहां भी है। अगर बहिन वहां है तो भाई यहां है । इससे यह समस्या जटिल हो जाती है । देश में कुछ ऐसा चलन है कि अगर हिन्दू विदेश से आएं तो वे शरणार्थी हो जाते हैं और अगर मुसलमान विदेश से आएं तो वे विदेशी हो जाते हैं बहुत लोगों की यही परिभाषा रही है । इस मामले को बहुत सहानुभूति-पूर्वक समझने की कोशिश करनी चाहिए । तात्कालिक तौर पर ही समझते हैं कि इस बिल को लाकर उन लोगों के दिमाग में सरकार यह बात रखना चाहती है कि वोट देने का अधिकार तो आपका समाप्त हुआ, लेकिन बाकी आपके सारे अधिकार सुरक्षित हैं । एक मायने में ऐसा किया जाना जरूर था । दूसरे मायने इसके यह भी हैं कि हम दो तरह के नागिरक इस देश में बना रहे हैं । एक तो वोट देने के अधिकार वाले नागरिक और दूसरे बिना वोट देने के अधिकार वाले नागरिक । यह दस वर्ष के बाद बालिग होंगे । यह बताया गया है कि एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा वह इन लोगों की जांच करेगा । इसकी भी कोई सीमा नहीं है । ऐसा लगता है कि हम लोग मामले में फंस गये हैं । साम्राज्यवादियों के कुचक्र में फंस गये है । फिर भी तात्कालिक तौर पर जिन लोगों को डिसफ्रेन्चाइज किया जाएगा, यह जरूरी था कि उनको बाकी

अधिकारों की सहूलियत दी जाय । इस अर्थ में इस बिल का समर्थन करता हूं । लेकिन जरूरत इस बात की है कि सर्वांगीण रूप से समस्याओं के निदान के लिए हम आगे बढ़ें । आसाम समझौते के अन्दर एक ही बिन्दू नहीं है । और भी कई बिन्दू हैं । उन बिन्दुओं का भी इंम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए । मैं समझता हूं कि आसाम के लोगों की पिछले कुछ वर्षों में और भी दयनीय स्थिति हो गई है । सिचाई की व्यवस्था आसाम में नहीं है । वर्षा भी अब बहुत ज्यादा इरेटिक हो गई है । मानसून भी बहुत अच्छा नहीं रहता है । लोग यही समझते हैं कि सबसे ज्यादा वर्षा आसाम में होती है । लेकिन सिचाई की व्यवस्था वहां पर राजस्थान को छोड़कर जितने भी हमारे पूर्वांचल के राज्य हैं, सबसे कम सिचाई का प्रबन्ध आसाम के अन्दर है । वहां बेरोजगारी की समस्या भी बहुत भयंकर हो गई है । वहां पर शिक्षा भी बहुत ज्यादा नहीं है । फिर भी पिछले दिनों के अन्दर शिक्षित बेरोजगारी की समस्या वहां पर बहुत बड़ी समस्या हो गई है जिसके चलते यह बवंडर और भी बढ़ा । यह भावना भी वहां पर पैदा हो गई कि आसाम के अन्दर गैर-आसामियों की बहुतायत हो जाएगी और वे लोग अल्पमत में हो जाएंगे । यह भावना तो वहां पर जरूर थी, लेकिन इसको और भी पैट्रोल दिया इस भावना को भड़काने का काम किया इस बेरोजगारी की समस्या ने । असम राज्य भारत के उन राज्यों में से है जहां पर कैपिटा इनकम सबसे कम है । वह एक सीमान्त राज्य है । किसी भी राज्य के टुकड़े टुकड़े कर देने से गरीबी दूर नहीं होगी । अगर ऐसा होता तो नागालैंड मेघालय और मनीपुर सभी बहुत खुशहाल हो गये होते । इसलिये यह धारणा जो काम कर रही है कि जितना छोटा राज्य हो जायेगा, उतनी खुशहाली होगी ठीक नहीं यह जरूरी नहीं है । खुशहाली तो इस बात पर निर्भर करती है कि कैसी आर्थिक व्यवस्था है । इसलिये मैं सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि असम की जो स्पेशल समस्या है, उसका कैसे समाधान हो, इस पर विचार किया जाय पिछले दिनों में असम राज्य बहुत नैगलेट रहा है, उसकी हम कैसे पूर्ति कर सकते हैं, इस पर विचार किया जाय । अभी भी मुझे याद है कि वहां के मुख्य मंत्री, जो शासक पार्टी के ही हैं, उन्होंने कहा था कि उनके लिये योजना में जो प्रावधान किया गया है वह बहुत कम है । सचमुच में ऐसे राज्यों के बारे में हमें विशेष ढंग से विचार करना चाहिए। मेरा तो ऐसा ख्याल है कि कुछ अन्य 5–6 राज्यों को जिस तरह से केन्द्रीय सरकार अनुदान के रूप में 90 प्रतिशत देती है और 10 प्रतिशत ही उन पर कर्जा रहता है उसी तरह से असम के बारे में प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि वहां लोन का हिस्सा कम हो और अनुदान का हिस्सा, सब्सिडी का हिस्सा योजना के अन्तर्गत जो दिया जाता है वह उनको ज्यादा दिया जाय और कुछ इस तरह विशेष ढंग से इस समस्या का निदान निकाला जाय । सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि असम राज्य में फिर चुनाव होने जा रहे हैं । मुझे विश्वास है कि तमाम राजनैतिक पार्टियां उसमें हिस्सा लेंगी । पिछले वर्ष कुछ ऐसी घटनायें घटित हुई थीं चुनाव के दौरान बहुत हत्यायें हुई, खून खराबा हुआ और कुछ लोगों ने जो इस प्रकार की घृणित घटनायें हुई उससे मजा लिया । मुझे आशा है कि इस समय जो वहां पर चुनाव हो रहे हैं इससे वहां भाई चारा बढ़ेगा और हम सब मिलकर काम करेंगे । जीत और हार तो प्रजातंत्र में लगा रहता है । लेकिन वहां जो एक नया प्रोसेस शुरू हो गया है यह एक स्वागत योग्य बात है और हमें उम्मीद है कि इसमें वहां के लोग आगे बढ़कर हिस्सा लेंगे । जहां तक वहां की समस्या के लिए इस बिल का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि सरकार ने जल्दबाजी में इस बिल को लाने की कोशिश की है और इससे एक बहुत ही छोटे से अंश की जो जरूरत थी उसकी ही पूर्ति हुई है । इसको और भी बढ़ाकर इस चीज को देखना चाहिए था कि उनकी समस्या के निदान के लिए आगे क्या ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि हम वहां की समस्या का हल निकाल सकें । मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर किसी भी हालत में नागरिकता के प्रश्न पर धर्म की बात नहीं आनी चाहिए जैसे कि यह हिन्दू है, यह मुसलमान है, यह ईसाई है । नागरिकता एक अलग विषय है

[श्री चतुरानन मिश्र]

और इसको इस बात को लेकर सोचना चाहिए कि हमारा देश सेकुलर है । इस बात पर हम गौर करें कि इसको हमने अपने संविधान में रखा है । जब हमारे राष्ट्र की आजादी का आंदोलन शुरू हुआ उस समय से हम यह प्रण लेते रहे हैं कि हमारा देश सेकुलर होगा, हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा । इसी सिद्धांत पर हमें आज भी अटल रहना है और इसकी पूर्ति के लिये आगे भी हमको प्रयास करना चाहिए । धन्यवाद ।

DR. MOHD. HASHIM KIDWAI (Uttar Pradesh): Madam Deputy Chairman, I rise to support the Citizenship (Amendment) Bill, 1985 which seeks to implement the Assam Accord and for which our dynamic Prime Minister deserves full praise, congratulations aid support. It opens up a new era in the history of Assam and let us hope that we will now have peace and normalcy in I Stat© which had, unfortunately, owing to the agitation, practically disappeared over the last five or six years. I am sure, with] *the,* Assam Accord and specially after the elections and installation of a new Ministry we will have not only peace in Assam but this State will march towards progress. Assam is a multi-racial, multi-lingual and multi-religious State. It is hoped that all the sections of population of this State will have a fair deal as is the characteristic feature of our motherland and as is th* |>oliey of our Prime Minister, and which, MT. Saikia, the Chief Minister of Assam, has consistently been following. It is very unfortunate that Assam which had the distinction of producing such illustrious sons* of India, like Fakhruddin Ali Ahmad, Opfratta Bardoli, T. R. Phukhan, Moinnl Haque Choudhury, Maulana Tyabullah, Chaliha and Bishnu Ram Mcdhi, should ►ave fallen a prey to chauvinistic, regional elements which posed a real danger and threat to our national unity and integrity. the need of the hour i9 to maintain tional unity and integrity in this bordw aad sensitive State like Assam and to fight these disruptive forces. This Bill «in*i at implementing the Assam accord. There can b© no two opinions that foreigners should not be allowed to enter and live in Assam and every possible effort should be made to drive out foreigners. But no Indian National should be turned out of Assam and therefore there should be some effective agency to check this. Unfortunately it has been brought to our n°tices that persons who had been living in Assam for years have been declared as foreigners by the police. The Home Ministry should see to it that these acts of injustice are not committed and a Special Cell should be set up in the Ministry of Home Affairs to see that no Indian national is declared as a foreigner.

There are one or two points which need some clarification. What will be the position of children who are born m 1966 or after 1966? What will be the service rights of those who have been disenfranchised? I hope that the Home Minister will clarify these points.

The insistence by Election Commission on birth certificates or production of names in the National Citizenship Register being taken a& proof of citizenship has caused great hardship, as millions of Indian citizens in other States do not possess the birth certificate, or no National Citizenship Register. is maintained in other States. The Home Ministry should enquire into al! this and review the cases of those persons who have been disenfranchised on this account. It will be better if the detection of foreigners is entrusted to judicial tribunals and I hope that Home Minister will consider this suggestion.

The second suggestion which I would like to! make is that another cell should be established in the Home Ministry to safeguard the interests of linguistic and religious minorities and to ensure all their rights. It should also ensure that where injustice is done against the minorities and any discrimination is done against them, the persons who are responsible-administrative authorities who are responsible for them are punished.

T hope and trust that Assam will have complete peace and normalcy and will march towards progress and the adoption of this Bill will go « long way in (restoring

normalcy and bringing peace and order to Assam and it will usher a new era. Thank you.

SHRI MAHENDRA PRASAD (Bihar): Madam, I give my whole-hearted support to thi$_s$ historic Bill—a Bill which is the instrument of codifying and legalising the attempted solution, and agreement thereon, of one of the knottiest and most turbulent problem's that the country has ever faced i$_O$ its 37 years °f sovereign existence. 1 heartily congratulate t'ne Government, and the Prime Minister in particular, for Slaving made a valiant attempt towards dawning peace and franquaillity on one of the most important and sensitive parts of our great country. The surprise agreement on the historic and auspicious day when 37 years ago oh that fateful day and almost at that very time our country rid itself from the shackles of "bondage and when the world slept in the dead and stillness of night, our country awoke into midnight freedom—o$_n$ the ticklish. Assam problem which made the country heave a great sigh of relief is Knottier mo colourful feather in the Prime Minister's cap after the magical surprise hut welcome, agreement on the enigmatic problem of Punjab. It i$_s$ another glittering jewel in the Prime Ministers crown of success.

Madam, I am not one $_0$f those who helieve that because $_0$f the agreement, everything has ended in Assam and Punjab and that we have brought $_a$ permanent solution to the tormenting and tortuous problems and that there will be no trouble there and there will be permanent peace and tranquillity. Peace and a permanent solution depend on 1. P.M. various factors, not necessarily within the control of $_a$ particular people and $_a$ particular Government; it (s often beyond them. It can also ne bred by foreign anti-social and disruptive forces; it can be the handiwork of power-hungry opposite parties $_a$nd forces. Tn spite of our agreement on the Punjab problem and in spite of the change of Government in Punjab, peace eludes Punjab; there is bloodshed, there are killings; fear and uncertainty still engulf our hope For peace and trnaquility in Punjab.

The credibility of the Central Government and the Assam agreement, and every one who contributed to this agreement, lies in the fact that a sincere attempt has been made to find a solution to a problem of such a magnitude that at times looked like threatening the unity of the country and the values, culture and everything that India stood for. The Prime Minister and other contributors to the agreement did not stand for prestige. Nobody lost; nobody gained. The gainer is the indomitable will of our people to have $_a$ united and strong India, the will to preserve our age-long value of *Vamdhaika Kutumbakam,* the will to have peace and tranquillity and living together with amity of various people of different castes, colours, features, regions and religions. That is great.

Madam, rhe Assam agreement has to be viewed in the back-ground of nightmarish mishaps of six long years—the black years of murders, killings, arso$_n$ loot, rape and creation of a barbaric atmosphare in Assam. Only he can truly appreciate and admire this agreement who has really seen an,d suffered from what happened during these tormenting and trying years. The land $_0$f civilization and culture where peace and tranquillity blossomed and bloomed like flowers, where there was amity and brotherhood among different sections of people, where language and religion were n$_0$ barrier to the confluence of love and unity of hearts—such a. great lands—suddenly rose to a reign $_C$'f terror where innocent people were killed, children were butchered, women were, raped, properties were burnt and looted, the economy was ruined anj disrupted, where the whole society rose to violence and the Iand of peace was pushed by thousands of years to $_a$ barbaric age where there was the disaster of Nelli and every dirty thing never known before.

I have paid several visits to Assam' during these years and I have seen and heard the stories of brutalities. It was here where peace was and is most demand, ing. It is here that this agreement win be remembered, admired and adored as an attempt to ushe$_r$ in a panacea of peace a«d goodwill,

[Shri Mahendra Prasad]

Assam, before the agreement, presented a scene of violence and turbulence where everyone suffered and the minorities of all shades and religions suffered the most. Attacks of all kind and perpetuation of a reign of terror on the minorities deserve condemnation by every section of peace-loving people. However, the Assam problem, unlike the Punjab problem, was complicated and to raise a finger of blame squarely only at any section of conflicting parties was difficult proposition. We should distinguish between the two agitations and the agitationists of Assam and Punjab. While the Punjab agitationists, it was often said, were and are unpatriotic and anti-national and inspired by outside forces, and with ulterior motives, the Assam agitators, according to the opinion of many, were not anti-national and unpatriotic and that they were not inspired by outside forces. Protagonists of the Assam agitation always claimed that their fear was genuine. I paid several visits to Assam and had several opportunities to talk to Assamese and they argued that they did not want to be harmful to others but that at the same time they did not want to be outnumbered and subsequently dominated and exploited, causing a psychology of fear of suffering and oppression in them. They conveyed to me their profound sense of apprehension and insecurity regarding the continuing influx of foreign nationals, Muslims and Hindus both, into Assam and their fear about the adverse effect upon the political, social, cultural and economic life of the State. They feared subjugation and domination. Their grievance was genuine and while Punjab agitationists were suspected and hated all over the country, a large number of people in the country, rightly or wrongly, had sympathy for the Assam agitationists and silently supported them—supported not their medium of violence but their cause, appreciating their doubts and apprehensions.

A look at the last census discloses that Assamese in Assam are already in minority and are out-numbered by the so-called minorities, if we take into consideration Muslims, Hindu Bengalis, Nepalis, tribals, Hindi-speaking peoples, Biharis, Oriyas and people from many other States together in Assam. If you talk to an agitating Assamese, they gag you and make you mum and speechless by quoting the example of Tripura. They say that the original people of Tripura have been outnumbered by the Bengali brothers and that original Tripuris are dominated in every sphere of their life—political, cultural, economic and social—by Bengalis. They say that now Bengali-dominated Tripura got the CPM Government in Tripura only because there is the CPM Government in West Bengal. They also say that Bengalis in Assam, by and large, are politically guided by West Bengal and that a large number of Bengalis in Assam are pro-CPM just because there is the CPM Government in Bengali-based-CPM Bengal. What answers do we have to their questions? On the face of that, minorities of both Hindus and Muslims have floated a party called/ the Minority United Forum for contesting elections. What if the MUF comes in power on the basis of their outgrown number and drive original Assamese out of Assam? They question. Their apprehensions are genuine. Let us put ourselves in their position and view the situation. They deserve our sympathy and understanding and not our hatred. At the same time, we cannot drive out minorities of all religions. Shades and regions out of Assam. Therefore, the situation in Assam is very complicated and it is very difficult to raise finger of blame on anyone. Both sides have very strong minus and plus points. It is like being caught between the horns of a dilemma. It is human problem. Both sides need sympathy and undersanding. The Assam agreement should be viewed in this light.

While viewing Assam problem we should not lose sight of the historic stark fuct that India faught a bloody was against Pakistan in 1971 just because we were flooded with refugees from East Pakistan and our economy and social life were threatened. We must remember that what happened in East Pakistan before the Indo-Pak war in 1971 was an internal affairs of Pakistan and had no

business to have a war against Pakistan on that count. But we were forced by the circumstances in which without war, we could not stop the influx of refugees into India threatening us economically, socially and probably politically. The Indo-Pak war of 1971 was a compulsion that was thrust upon India.

Madam, we have given protection to the people of Kashmir. Though Kashmir is a part of India, people from other parts of India are legally debarred from acquiring landed property in Kashmir. Our brethren of Kashmir have got constitutional protection and safeguard. People from other parts of the country cannot acquire landed property in Meghalaya, the home State of our Minister of State for Home Affairs, Mr. Sangma, who is to reply to this debate.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You better conclude your speech, then, he will reply.

SHRI MAHENDRA PRASAD: Our brothers of Meghalaya have got constitutional safeguards. Nobody resents them. If our brothers of Assam get the same safeguard and protection for the same reason to mitigate the fear of domination and being out-numbered, it is a welcome step.

Madam, let the Assam accord be codified and legalised by the passage of this Bill; let there be panacea of peace and tranquillity in the great and beautiful land of Assam. I support the Bill as it is a valiant attempt to usher in peace and traiquility in Assam. Let us discard ourselves of all prejudices and biases let us have sympathy; let us support this bill as a good attempt for peace.

Madam, before I close my speech, I have an apprehension which I want to put on the record of the House. What happens to the execution of Assam agreement if the ensuing election results in a chocie of unstable Government or a Government by A.G.P.? What happens if any such Government, not committed heart and soul, flouts the Assam agreement and throws minorities out of Assam indulging in and encouraging disruptive and violent forces?

Thank you.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF STATES (SHRI P. A. SANGMA): Madam, I thank the hon. Members for giving us this very interesting debate on this very important Bill. The debate yesterday started with self-contradictory statements by our hon. friend from C.P.M., Mr. Mohanan. We also witnessed a very emotional speech by Mr. Hashmi, very impressive speech by my hon. friend, Mr. P. Babul Reddy and a very good speech by Prof. Lakshmanna.

Madam, Assam accord is a political accord. As I stated earlier, this Bill only seeks to give a legal shape to a portion of the settlement which relates to the foreigners.

This Assam accord has been widely welcomed in the whole country. It has been welcomed by this House and the other House. It was very clear in this debate that every hon. Member had welcomed the Assam accord. As my hon. friend, Mr. P. Babul Reddy has very rightly pointed out yesterday that those who have welcomed this accord cannot oppose this Bill; and those who are opposed to this Bill cannot support this accord. It is in this context I have said that our hon. friend was little contradictory when he said that we welcome the accord, but oppose the Bill. I think those who welcome this Bill has no room to oppose this Bill.

Now, a number of points have been raised about depriving the minorities or disenfrachisement and all sorts of things. Madam, I want to make it very clear that this Bill does not deal with the minorities of any kind. This Bill deals purely with a matter relating to the foreigners. When we talk about foreigners, there is no room for us to discuss about minorities—whether it is religious or linguistic.

[Shri P. A. Sangma]

A *foreigner* is a foreigner. He may be speaking any language; he may be professing any religion. But a foreigner is a foreigner. We are dealing, in this Bill, only with matters relating to foreigners. Secondly, ft must be made very clear that we are not discussing about taking away anybody's right. There is no question of disenfranchising. There is no question of deprivation. Ther$_e$ is no question of taking away anybody's right here. On the other hand, we are conferring rights on the foreigners who hav$_e$ come to our country and whom we are accepting. This Bill deals with two categories of people. One is, those people who had come on or before 1-1-1966, and we are conferring citizenship on these people by this Act at a stroke. They do not have, to go through any process. Therefore, it is conferment of rights that we seek *to* do. There is no question of taking away anybody's right. The second category of people are those who have come, between 1-1-1966 and 24-3-1971. This is the second category of people on whom we are going to confer citizenship after ten years from the day they have been detected as foreigners. Where is the question of taking away anybody's right? Where is the question of disenfranchising a large number of people, as somebody had alleged? There is no question of disenfranchising anybody. This is a question of giving citizenship rights with-retrospective effect, that is, from 1-1-1966 and conferring citizenship rights with prospective effect, that is, after 10 years from the day they have been detected as foreigners. This is very simple.

Now, the question is whether Parliament has the authority, has the right to confer these rights on the people. So many points on the constitutional validity or the constitutionality of this Bill have been discussed. I think many hon. Members from this side and the other side, including thmk Mr. Babul Reddy himself, have pointed out tbat Parliament is competent to decide on all matters relating fo citizenship. And this has been very clearly, very expressly, unambiguously, p»t forward in article 11 of the Constituton of India. It says:

> "Nothing in the foregoing provisions of this Part shall derogate, from tbe Power of Parliament to make any' provisions with respect to the acquisition and termination of citizenship. . .

1 want to underline this;

"and al) other matters relating to citizenship." Therefore, the constitutionality of this Bill cannot be doubted. The power of Parliament to enact such a Bill cannot be challenged at all. Now on© pertinent question, of course, remains. An allegation has been made that this Bill is creating two types of citizenship. I do not know where are the tw^ types of. citizenship. Those people who had come on or before 1-1-1966 will become citizens immediately when this Bill comes into force. And those people who have come between 1-1-1966 and 24-3-1971, both days inclusive, will become citizens of this country after ten years from the day they have been detected as foreigners. Where is the question of two types of citizenship?' The question is, till they become citizens of India after ten years from the date of detection, what will happen to *them,* whether they will be able to enjoy all the right, since they are not citizens, since they are going to become citizens after ten years. This is $_a$ pertinent question.

SHRI S. W. DHABE (Maharashtra): Today they are voting in the elections. Is it a fact or not?

SHRI P. A. SANGMA: 1 am discussing the constitutionality, whether Parliament has the right to confer other rights *em* these people till they become full-ffedged citizens. And this provision has also bee* made very clear in section 12 of the Citizenship Act, which 1 would like *to* quote

for the benefit of the hon. Member. Section 12 reads:

> "The Central Government may, by order notified in the Official Gazette [33]

—by a simple order—

> "...make provisions on a basis of reciprocity for the conferment of all or any of the rights of a citizen of India on ihe citizens of any country specified in the First Schedule."

The First Schedule lists the members belonging to the Commonwealth. Bangladesh was not added in the First Schedule af that time because it has come only recently; otherwise, this could have been done by a mere notification under this provision. Therefore, there is no question having two categories of citizens as has been talked about. Even, for the sake of argument, if you concede about the right to franchise, it is onething to be a citizen of India and it is quite another thing to be a voter. It is not that all citizens of this country are entitled to vote. It is only when one attains the age of 21 under Article 326 that one is eat'tued to franchise. But do you mean to say that those who are below 21 are not citizens of this country? *(Interruptions)* I am just talking about the legal points.

Another point made is that this Agreement has/ been reached in spite of the international commitment, which obviously to the Liaqat-Nehru Pact and the Mujibur-Indira understanding etc. I must inform the honourable House that all these aspects have been fully taken care of before this Agreement has been reached Para 4 of the Accord says:

> "Keeping all aspects of the problem, including constitutional and legal previsions, international agreements, national commitments and humanitarian considerations, it has been decided to proceed as follows... '*"

Therefore, all these aspects have been taken into consideration.

Another point made was that the Government has gone back from what Mrs. Gandhi promised, that Mrs. Gandhi said < that 1971 should be the cut-off year. *Ot* course, this point was very effectively answered by my senior colleague, Mr. Baharul Islam that Mrs. Gandhi had never agreed that 1971 should be the cut-off year. What she bad always said was that we, could start with 1971. that 1971 could be a starting Point. This was what Mrs. Gandhi had said. So there is no question of soing back from wha' Mrs. Gandhi had said.

Many other points have been raised, particularly by Professor. It has been a very, very, well-areued speech vesterday and Professor has been very kind to point out many other provisions of the Accord and why the Government has not been doing anything in that respect. One particular thing which he quoted was para 6 where it says:

> "Constitutional, legislative, administrative, safeguards as may be appropriate, shall be provided to protect, preserves and promote the cultural, social, linguistic identity and heritage of the Assamese people."

In a written answer to one of the Parliamentary questions I think 1 had given a background of this whole thing. During the Agreement, during the discussions, during the negotiations, it was agreed that the AASU leaders will submit a proposal as to hi what manner they want their lights aad their culture, their heritage and identity to to be preserved, they are supposed to give . us a proposal and we are waiting for their proposal and as soon as their proposal comes, we will certainly examine it. Either my answer was not seen by hirn or it did not give the background clearly. You have every reason to misunderstand it. I think it is my fault, it wa? not your fault . I can only say ...

PROF. L LAKSHMANNA: My only point was flat under a similar accord elsewhere, we went out of the way and announced certain things like a dam, a cultural centre and a coach factory and so on, which were not asked for by them. But, ..; of Assam, ?.re are not com-

[Prof. C. Laksmanna]

ing forward with such ' assurances or announcement of establishment ot' institutions by which the cultural identity of Assam could be maintained. That is all.

SHRI P. A. SANGMA: r can only assure the House and the people of Assam, that we are committed to the all-round development of Assam. We have full commitment to every provision of the accord and we are going to implement it in letter and spirit and this I car* say on the floor "of the House. There is no question of not implementing any provisions of the accord. Every provision of the accord will be implemented nnd we have already taken a number of steps and if I go on telling what steps have been taken against each para of the accord, it will take a Ions time. But I can only assure the House that we ar» committed to the development of Assam and, in fact, if look at the figure for the Seventh Five Year Plan, you will see that the Seventh Plan outlay for Assam has been finalised at Rs. 2,100 crores as against the Sixth Plan figure of Rs. 1,115 crores. So, the Seventh Plan outlay is almost double that of the Sixth

PROF. C. LAKSHMANNA (Andhra Pradesh*):* This is thfe of almost all the States.

SHRI P. A. SANGMA; No, Professor if is not true. In the case ol ihe most of ihe backward States, yes, it js so. I think it is true of most of the North Eastern- Stales because a special effort is being made to develop them. It is not confined to Assam alone, but it applies to some other States of the North-Eastern Region. To that extent. Madam, the Professor is right.

Another point that is to be noted is that out of this amount of R 2,100 crores. Central assitance will be to e tun* of Rs, 2,065 crores which means that practically tbe whole of the Seventh, Plan is being financed by the Central Government. 1 am giving a little illustration only to show tfiat we aft certainly committed to the development of Assam and, for that matter, all parts of the country. But we are making special efforts to develop Assam in view of the promises that we has in this accord.

With these words, Madam, I once again thank all the honourable Members and I request that the Bill may be passed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Ihe question is:

"That the Bill further to amend the Citizenship Act, 1955, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN; W now take up the clause-by clause deration of the Bill. There are three amendments to clause 2. Mr. Malaviya to move his, amendment.

Clause 2—*Insertion cf new section €A,*

श्री राम प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि :

"पृष्ठ 2 पर पंक्ति 15 में 'अभिन्न' शब्द के स्थान पर 'संयुक्त' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए ।"

मैं चाहता हूं कि मेरी यह अमेंडमेंट स्वीकार कर लेनी चाहिए । क्लाज (1) सब क्लाज डी में मेरा यह सबमिशन है कि अनडिवाइडिड इंडिया जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए । इसको आपको युनाइटेड इंडिया कहना चाहिए । 15 अगस्त, 1947 को जब देश आजाद हुआ, बटवारा हुआ तो उस वक्त हमने इसको युनाइटेड इंडिया के रूप में स्वीकार किया था । आप इसको यहां पर युनाइटेड इंडिया रख दें तो अच्छा है । आपको मेरी यह अमेंडमेंट स्वीकार कर लेनी चाहिए ।

The question was proposed

SHRl P. A. SANGMA: Madam. ihe word 'undivided' has been used in the Citizenship Act, 1955. and that word has

been defined in the Act itself. Therefore, we cannot substitute this word at this stage because the main Act itself defines that word. So it is not possible for us to ac-:ept this.

SHRI BAHARUL ISLAM (Assam): Only one minute. 'Undivided' is one solid thing. 'Undivided' is used when two :ire united. 'Undivided' is cor-rect. So, the word" 'undivided* -------

(Interuptioos)

THE DEPUTY CHAIRMAN: The juestion is:

"That at page 2 line 6, for the 'undivided' the word 'ununited- be substituted.

The Motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There we two amendments by Shri Asad Ma-lam. He is not here.

Now. the question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 *was added to the Bill.*

Clause 1 *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI P. A. SANGAMA: Madam, I nove :

t the Bill be passed."

The question was put and the motion van adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The louse stands adjourned till 2.30 for lunch.

The House then adjourned for lunch at thirty-two minutes past one of the clock.

Tbe House reassembled after lunch at thirty-two minutes past two cf the clock,

Tbe Vice-Chairman (Shri Pawan, Bansal) *n* the Chair.

REGARDING GOVERNMEN!' MO-TION REGARDING THE REPORTS OF THE COMMISSIONER AND COMMIS-SION FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES.

THE VICE-CHAIRMAN , (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL) :* Now, we will take up the Government motion.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY. OF WELFARE (SHRI-MATI RAJENDRA KUMARI BAJPAI): Sir, I beg to move the (following Motion:

"That the Twenty-third. Twenty-fourth. Twenty-fifth. Twenty-sixth Twenty seventh Reports of the Com-missioner for Scheduled Castes :-.nd S duled Tubes pananning io tne years 1974-75. 1975—77. (1975-76 and 1976-77). 1977-78, 1978-79 and 1979-81 (1979-80 and 1980-81). laid on Table of the Rajya Sabha on 2nd March. 1978, 11 the May, 1978, 2nd February 1980, 22nd December, 1980 and 13th August, 1982, respectively and the First Second. Third and Fourth Reports of the Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1978-79, 1979-80, 1980-81 and 1981-82 laid on the Table of the Rajya Sabha on 23rd December. 1980. 13th August, 1982, 10th August. 1984. and 24th January, 1985, respec-tively, be taken into consideration."

As the Commission ind ihe Commis-sioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are looking after the progress what the Government is doing in this sphere, I will request the House to discuss all the reports together though som_e of the reports were laid on the Table of the House mor_e than 10 years back. As' per th_e rules, we have to discuss it. The Gov. ernment will be benefited by the obse tions of th_e hon. Members", whatever T have to say i will say at the end cf the debate. Now, I request the House to consider it.

*SHRIMATI ILA BHATTACHARYA (Tripura): Hon. Mr. Vice-Chairman, first of all. I would like to congratulate our new Minister, Shrimati Rajendra Kumar Baj-pai. She visited my state a few times.

* English translation of the original speech delivered in Bengali.